रेसपिी फॉर अ लविबिल प्लेनेट रपिोर्ट: वशि्व बैंक

प्रलिमि्स के लयि:

कारबन सीक्वेस्ट्रेशन/पृथक्करण, कृषि के कारण उत्सरजन, ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन, UNFCCC, कारबन क्रेडटि, शुद्ध शून्य उत्सरजन, पर्यावरण पारसि्थतिकि से संबंधति सामान्य मुद्दे, जलवायु परविर्तन, कृषि के कारण ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन

मेन्स के लयि:

कृषि के कारण उत्सरजन, कृषि खाद्य उत्सरजन का न्यूनीकरण

स्रोत: वरल्ड बैंक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वशि्व बैंक ने एक **"रेसपिी फॉर अ लविबिल प्लेनेट" नामक एक रपिोर्ट जारी** की, जसिमें स्पष्ट कयिा गया है कि **वर्ष 2030 तक कृषि खाद्य उत्सरजन को आधा करने के साथ ही वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के लयि 260 बलियिन अमेरकिी डॉलर का वार्षकि नविश** आवश्यक है।

- रपिोर्ट में स्पष्ट कयिा है कि यह आँकड़ा वर्तमान में कृषि सब्सडिी पर **व्यय की जाने वाली राशि का दोगुना** है।

रपिोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं?

- **परचिय:**
  - **"रेसपिी फॉर अ लविबिल प्लेनेट रपिोर्ट"** जलवायु परविर्तन पर कृषि खाद्य प्रणाली के प्रभाव को कम करने हेतु एक **वैश्वकि रणनीतकि ढाँचा** प्रदान करती है।
  - यह रेखांकति करती है कि कैसे वशि्व का खाद्य उत्पादन **वैश्वकि खाद्य सुरक्षा सुनशि्चति करते हुए** ग्रीनहाउस गैस (GHGs) उत्सरजन को कम कयिा जा सकता है।
- **कृषि खाद्य प्रणाली सुधार की संभावनाएँ एवं लाभ:**
  - **कमी की संभावना:** वैश्वकि **कृषि खाद्य प्रणाली व्यवहार्य एवं सुलभ उपायों के माध्यम से** वैश्वकि रूप से **GHG उत्सरजन का लगभग एक तहिाई कम** कर सकती है।
    - ये उपाय खाद्य सुरक्षा को सुनशि्चति करने के साथ-साथ खाद्य प्रणाली पर जलवायु परविर्तन के प्रभाव को कम कर सकते है, जसिसे **सुभेद्य समुदायों की सुरक्षा** प्राप्त होगी।

//

⁝ 1.1 Greenhouse Gas Emissions from the Agrifood System Are Significantly Higher than Previously Thought

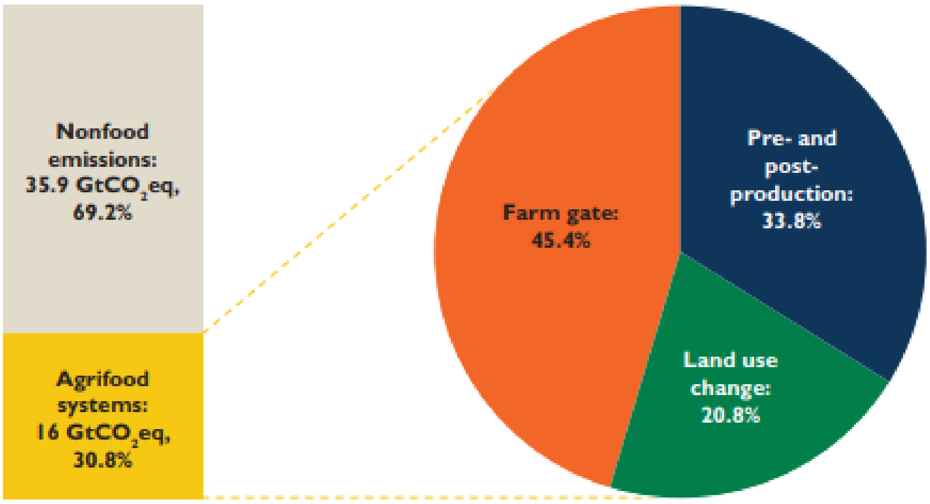

- **जलवायु परिवर्तन में कृषि खाद्य की भूमिका:**
    - **उत्सर्जन में योगदान:** कृषि खाद्य वैश्विक **GHG उत्सर्जन में लगभग एक तिहाई** का योगदान देते है, जो विश्व की कुल ऊष्मा एवं बिजली उत्सर्जनों से अधिक है।
    - **उत्सर्जन के मुख्य योगदानकर्त्ता:** इनमें से लगभग तीन-चौथाई उत्सर्जन विकासशील देशों से उत्पन्न होता है,जिससे **क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार, लक्षित शमन कार्रवाई की आवश्यकता होती है।**
    - **खाद्य मूल्य शृंखला से उत्सर्जन:** भूमि उपयोग परिवर्तन सहित संपूर्ण **खाद्य मूल्य शृंखला** से उत्सर्जन को संबोधित करना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि आधे से अधिक उत्सर्जन कृषि स्तर से परे होते हैं।

Positive Feedback Loops between Agrifood Activities and the Climate Have Created a Vicious Circle that Precludes Adaptation Alone as a Solution to the Crisis

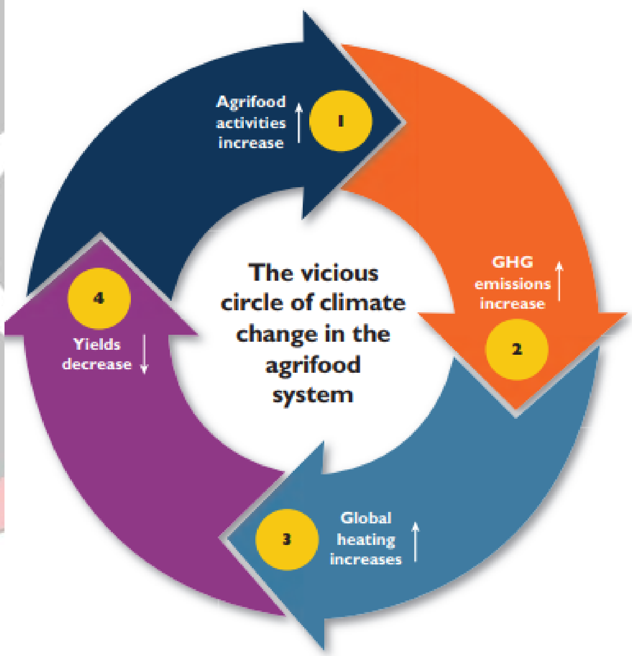

रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं?

- **आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ:**
    - **अप्रयुक्त क्षमता:** कृषि खाद्य क्षेत्र जलवायु कार्रवाई के लिये महत्त्वपूर्ण, लागत प्रभावी अवसर प्रदान करती है, जिसमें उन्नत भूमि प्रबंधन के माध्यम से वातावरण से कार्बन प्रग्रहण भी शामिल है।
    - **निवेश पर रिटर्न:** वर्ष 2030 तक कृषि खाद्य उत्सर्जन को आधा करने के लिये आवश्यक वित्तीय परिव्यय से पर्याप्त रिटर्न प्राप्त

होगा, जो स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर लाभकारी प्रभाव के साथ लागत से कहीं अधिक होगा।

- **देशों और विश्व स्तर पर कार्रवाई के अवसर:**
  - **उच्च आय वाले देशों की भूमिका:** इन देशों को **अपनी कृषि खाद्य ऊर्जा माँगों को कम करना चाहिये, वित्तपोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण** के माध्यम से निम्न आय वाले देशों का समर्थन करना चाहिये तथा उच्च उत्सर्जन वाले खाद्य पदार्थों से दूर उपभोक्ता आहार को संशोधित करना चाहिये।
  - **मध्य-आय वाले देशों की भूमिका:** ये देश बेहतर भूमि उपयोग प्रबंधन और कृषि पद्धतियों के माध्यम से महत्त्वपूर्ण उत्सर्जन में कमी ला सकते हैं।
  - **निम्न आय वाले देशों की भूमिका:** उच्च उत्सर्जन वाले बुनियादी ढाँचे के बोझ के बिना सतत् विकास पर ध्यान केंद्रित करना, उत्पादकता और लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिये कृषि वानिकी जैसी रणनीतियों का भी लाभ प्राप्त होना चाहिये।
- **देश और वैश्विक स्तर पर कार्रवाई:**
  - **निवेश और नीति पहल: कृषि खाद्य शमन में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाना, सब्सिडी का पुनर्वितरण करना तथा न्यून उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों के उपयोग की नीतियों को लागू करना।**
  - **नवाचार और संस्थागत समर्थन:** उत्सर्जन डेटा के लिये डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना तथा कृषि खाद्य प्रणाली को बदलने के लिये नई प्रौद्योगिकियों में निवेश करना, जिससे उचित परिवर्तन के लिये समावेशी हितधारक भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

FIGURE B3.1.1 India's Agrifood System Emissions, 1990–92 and 2018–20

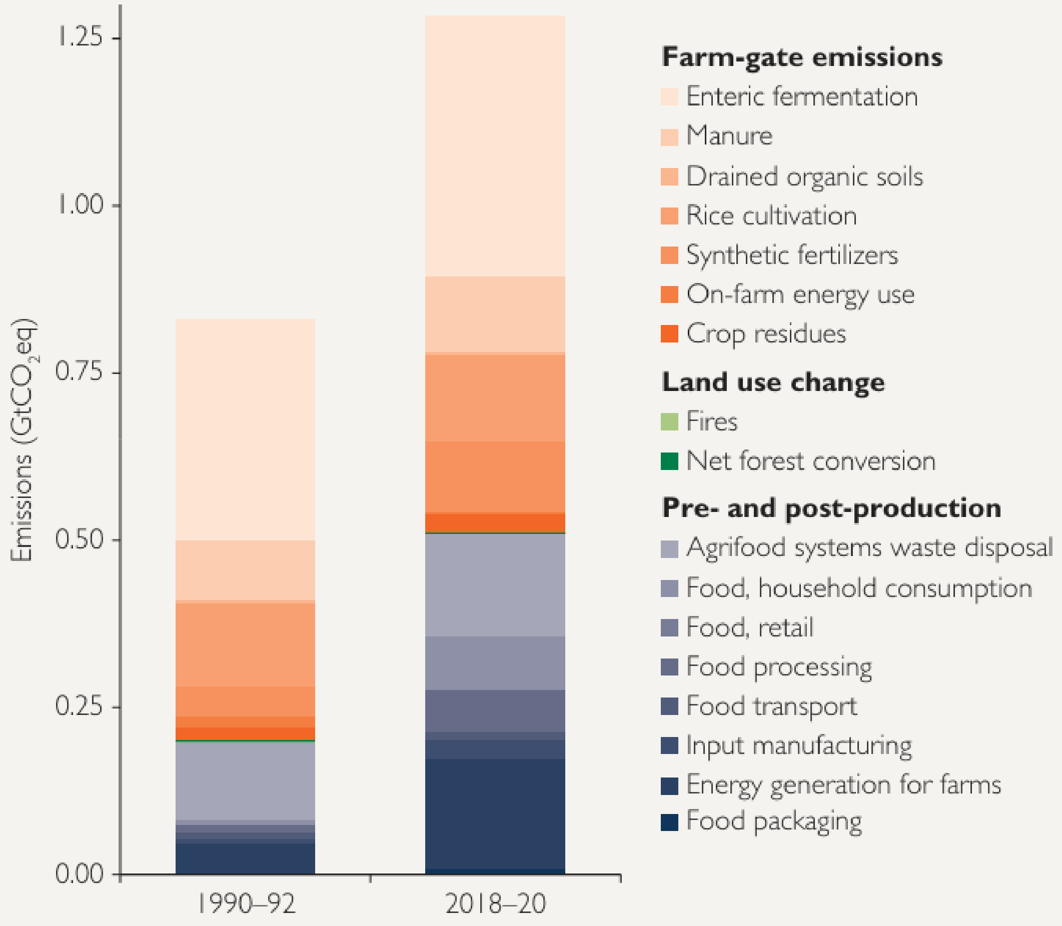

Source: Data from World Bank and FAOSTAT 2023c.
Note: $GtCO_2eq$ = gigatons of carbon dioxide equivalent.

रिपोर्ट में भारत से संबंधित मुख्य बिंदु क्या हैं?

- **वैश्विक कृषि खाद्य उत्सर्जन में भारत का योगदान:**
  - रिपोर्ट में भारत को **चीन और ब्राज़ील** के साथ **कुल वार्षिक कृषि खाद्य प्रणाली उत्सर्जन** के मामले में **शीर्ष 3 देशों में से एक के रूप** में पहचान मिली है।
- **भारत में लागत प्रभावी शमन क्षमता:**
  - रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जैसे देशों में कृषि में लगभग 80% तकनीकी शमन क्षमता अकेले **लागत-बचत उपायों को** अपनाकर प्राप्त की जा सकती है।
    - यह भारत के लिये उत्सर्जन को कम करने के साथ-साथ कृषि उत्पादकता एवं आय में सुधार करने का एक बड़ा अवसर है।

- **भारत के लिये प्रमुख शमन विकल्प:**
  - भारत के लिये प्रमुख शमन विकल्पों में **बेहतर पशुधन आहार (**[हरित धारा, एक एंटी-मिथेनोज़ेनिक चारा]**)** और प्रजनन, उर्वरक प्रबंधन तथा जल सघन फसलों में बेहतर जल प्रबंधन शामिल हैं।
    - भारत के कृषि क्षेत्र के लिये **सीमांत उपशमन लागत वक्र** से पता चलता है कि ये कुछ सबसे अधिक लागत प्रभावी उपाय हैं जिन्हें भारत वर्ष 2030 तक **कृषि खाद्य उत्सर्जन में काफी हद तक कमी करने** के लिये अपना सकता है।
    - भारत को कृषि उत्पादन से [मीथेन उत्सर्जन] पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है।
    - **धीरे-धीरे सिंचाई करने जैसी पद्धतियों** को अपनाने तथा कम मीथेन उत्सर्जित करने वाली फसल किस्मों को वृद्धि करने से उत्सर्जन शमन के अवसर मिलते हैं।
  - भारत में भोजन हानि और बर्बादी की दर उच्च है। [खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2021] के अनुसार, भारतीय परिवार **प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 50 किलोग्राम** खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं।
    - भारत में खाद्य हानि और बर्बादी को कम करने के साथ-साथ अन्य उच्च प्रभाव वाले अवसरों से आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता:** भारत को अपनी कृषि-खाद्य शमन क्षमता के लिये **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और तकनीकी सहायता** की आवश्यकता होगी।

FIGURE 0.11 Governments, Businesses, Civil Society Groups, and International Organizations All Have Roles to Play in Scaling Climate Action

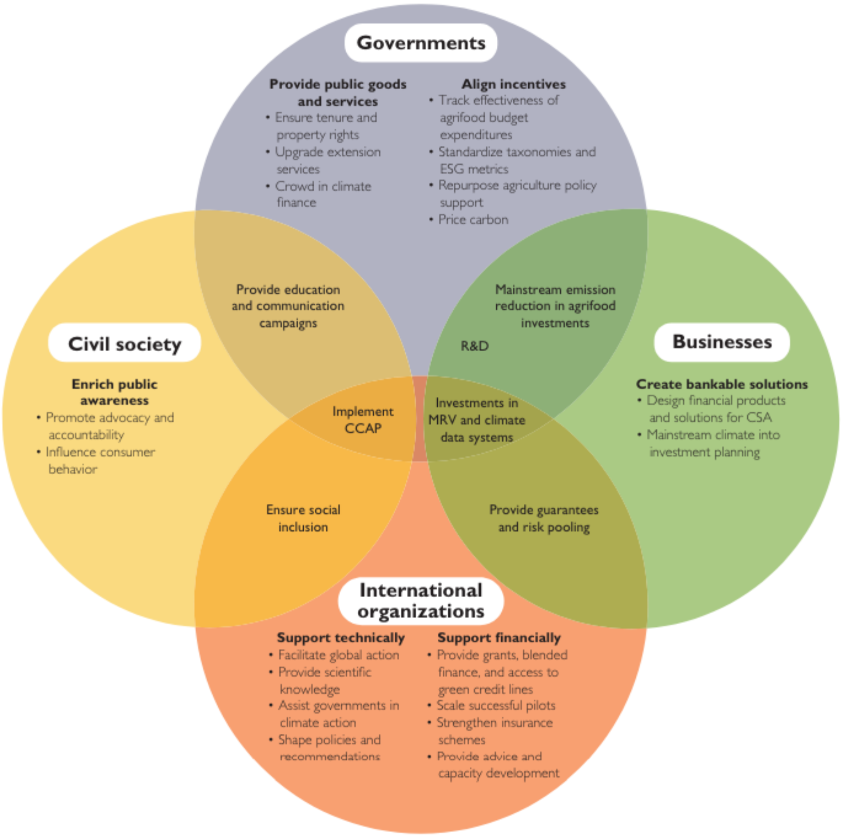

आगे की राह

- **निवेश:** सरकारों और व्यवसायों को मिश्रित वित्त, कॉर्पोरेट जवाबदेही तथा विस्तारित कार्बन बाज़ारों के माध्यम से कृषि खाद्य में **निजी जलवायु निवेश को जोखिम से मुक्त** करना चाहिये।
- **प्रोत्साहन:** नीति निर्माताओं को **कृषि खाद्य प्रणाली परिवर्तन** जैसे हानिकारक सब्सिडी का पुन: उपयोग करना और नीति सुसंगतता सुनिश्चित करने में तेज़ी लाने के लिये उपायों को लागू करना चाहिये।
- **जानकारी: डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके GHG निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन (MRV) प्रणालियों में सुधार करने से क्षेत्र के लिये जलवायु वित्त को उपलब्ध कराने में सहायता मिल सकती है।**
- **नवाचार:** लागत प्रभावी शमन प्रौद्योगिकियों का विस्तार और अनुसंधान एवं विकास निवेश में वृद्धि से कृषि खाद्य प्रणालियों के भविष्य में परिवर्तन को बढ़ावा मिल सकता है।
- **संस्थाएँ: अंतर्राष्ट्रीय ढाँचे, राष्ट्रीय नीतियों और उपराष्ट्रीय पहलों** को समन्वित तरीके से कृषि खाद्य शमन के अवसरों को सुविधाजनक बनाना चाहिये।
- **समावेशन:** परिवर्तन को हितधारक जुड़ाव, लाभ साझाकरण और सामाजिक सशक्तीकरण के माध्यम से छोटे किसानों जैसे कमज़ोर समूहों की रक्षा

करके एक उचति परविर्तन सुनशि्चति करना चाहयिे ।

दृष्टि The Vision

संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियाँ- UNSAs

Part V (IMF, World Bank तथा UNESCO)

UNSAs संयुक्त राष्ट्र के साथ कार्य करने वाले 15 स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

- स्थापना - 1944 (1930 के दशक की महामंदी के बाद संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन)
- मुख्यालय - वाशिंगटन DC, USA
- कार्य -
  - » वैश्विक वित्तीय सहायता
  - » अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना
  - » विकासशील देशों के लिये वित्त पोषण
  - » विनिमय दर स्थिरता को बढ़ावा देना
- सदस्य - 190 (भारत इसका संस्थापक सदस्य)

भारत के वित्त मंत्री IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में पदेन गवर्नर हैं

- विशेष आहरण अधिकार (SDR) -
  - » IMF की आरंभिक आरक्षित परिसंपत्तियाँ अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार को परिशिष्ट करने के लिये हैं (न कि मुद्राओं को)

SDR बास्केट में मुद्राएँ - $ (डॉलर), € (यूरो), £(पाउंड), ¥ (येन) और CN¥ (रॅन्मिन्बी)

- IMF कोटा -
  - » विश्व अर्थव्यवस्था में एक सदस्य देश की सापेक्ष स्थिति को दर्शाता है (भारत - 2.75%)
  - » SDR में नामांकित
- प्रमुख प्रकाशन -
  - » वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक
  - » वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
  - » फिस्कल मॉनिटर
  - » एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट

विश्व बैंक समूह (WBG)

- स्थापना- IMF के समान
- मुख्यालय- वाशिंगटन DC, USA

WBG के 5 संस्थान (स्था.)	कार्य
अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) अर्थात् विश्व बैंक (1944)	ऋण, लोन एवं अनुदान प्रदान करना
अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) (1956)	कंपनियों या सरकारों को निवेश, सलाह एवं परिसंपत्ति प्रबंधन
अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) (1960)	कम आय वाले देशों को कम ब्याज दर पर या ब्याज रहित ऋण प्रदान करना
निवेश विवादों के निपटारे के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID) (1966)	निवेश-विवादों का समाधान करना
बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA) (1988)	राजनीतिक जोखिमों से ऋणकर्त्ताओं या निवेशकों को संरक्षण

IMF की सदस्यता IBRD की सदस्यता के लिये एक पूर्व शर्त है

- WBG के दोहरे लक्ष्य -
  - » वर्ष 2030 तक अत्यंत निर्धनता को समाप्त करना
  - » सभी देशों में सबसे निर्धन 40% आबादी की समृद्धि को बढ़ावा
- सदस्य - 189 (भारत IBRD, IFC और IDA के संस्थापक सदस्य है)

भारत ICSID का सदस्य नहीं है; भारत का मानना है कि यह विकसित देशों के प्रति झुकाव रखता है

- प्रमुख प्रकाशन -
  - » मानव पूंजी सूचकांक
  - » विश्व विकास रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO)

- स्थापना- 1945 {CAME द्वारा प्रस्तावित (कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन)}
- मुख्यालय - पेरिस, फ्रांस
- विशेषज्ञता के क्षेत्र -
  - » शैक्षिक विकास (पूर्व-विद्यालय से उच्च शिक्षा तक)
  - » धरोहर का संरक्षण, रचनात्मकता को बढ़ावा
  - » एक सतत् भविष्य के लिये विज्ञान
- UNESCO की वैश्विक प्राथमिकताएँ -
  - » अफ्रीका
  - » लैंगिक समानता
- सदस्य - 193 (भारत सहित) + 11 सहयोगी

USA UNESCO का सदस्य नहीं है

- महत्त्वपूर्ण पहलें -
  - » विश्व धरोहर सम्मेलन और विश्व धरोहर स्थलों (WHS) की सूची (भारत में 40 WHS हैं)
  - » मैन एंड द बायोस्फीयर (MAB) कार्यक्रम
  - » इंटरनेशनल जियोसाइंस एंड ग्लोबल जियोपार्क्स प्रोग्राम (IGGP)
  - » अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर (ICH) पर सम्मेलन

भारत ने ICH समिति के सदस्य के रूप में दो बार सेवा की है

- महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट -
  - » UNESCO विज्ञान रिपोर्ट
  - » वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट
  - » भारत के लिये UNESCO स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट: चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

वशि्व स्तर पर शीर्ष उत्सर्जकों में से एक होने की स्थिति को देखते हुए, भारत कृषि खाद्य प्रणाली से अपने उत्सर्जन को कैसे कम कर सकता है? स्थिरिता और खाद्य सुरक्षा के लिये संभावित रणनीतियों तथा उनके निहितार्थों पर चर्चा कीजिये।

UPSC सिविलि सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. कभी-कभी सामाचारों में आने वाली 'गाडगिल समिति रिपोर्ट' और 'कस्तूरीरंगन समिति रिपोर्ट' संबंधित हैं: (2016)

(a) संवैधानिक सुधारों से
(b) गंगा कार्य-योजना से
(c) नदियों को जोड़ने से
(d) पश्चिमी घाटों के संरक्षण से

उत्तर: (d)

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये- (2021)

1. 'शहर का अधिकार' एक सम्मत मानव अधिकार है तथा इस संबंध में, संयुक्त राष्ट्र हैबटिट (यू. एन. हैबटिट) प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है।
2. 'शहर का अधिकार' शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने (रीक्लेम) एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है।
3. 'शहर का अधिकार' का आशय यह है कि राज्य, शहर की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 3
(c) 1 और 2
(d) 2 और 3

उत्तर: (c)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/recipe-for-a-livable-planet-report-of-world-bank